नक्की झील पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया

मुख्यमंत्री ने आबू राज को सांस्कृतिक विरासत, प्रकृति व आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बताया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिरोही जिले के आबू राज में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में योगाभ्यास किया।

■ आबू राज में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल ने उपस्थित जनसमूह को मन की स्थिरता, आत्म विश्वास, कर्तव्य निष्ठा, समाज व विश्व में शांति, आनंद एवं स्वास्थ्य के संवर्धन के लिये प्रतिबद्ध रहने की शपथ दिलाई।

आबू राज/जयपुर, 21 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिरोही जिले के आबू राज में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोलकाता में दिए गए संबोधन को भी सुना।

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अरावली की पावन गोद में बसा आबू राज अध्यात्म की भूमि है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति तथा आत्मिक शांति का अद्भुत संगम है। यहां की निर्मल वायु, हरियाली और आध्यात्मिक वातावरण योग की मूल भावना को साकार करते हैं।

उन्होंने कहा कि देश ने योग को कर्म योग से जोड़कर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के तौर पर विकास की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। आज योग विश्वव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा, यह गर्व का विषय है कि हमारी प्राचीन योग की परंपरा मानवता के कल्याण का वैश्विक माध्यम बन चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग' है। इसका संदेश यह है कि योग केवल युवाओं तक सीमित नहीं, बल्कि यह बढ़ती उम्र के लोगों को भी शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से संतुलित और भावनात्मक रूप से मजबूत रखने का सशक्त माध्यम है।

अरावली की वादियों में नक्की झील के किनारे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को मन की स्थिरता, आत्मविकास, कर्तव्यनिष्ठा तथा समाज और विश्व में शांति, आनंद एवं स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध रहने की शपथ दिलाई। साथ ही, सफेद गुब्बारे उड़ाकर विश्व शांति एवं निरोगी राजस्थान का संदेश दिया गया।

इस दौरान पंचायतीराज राज्य मंत्री ओटा राम देवासी, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री केके विश्नोई, सांसद मदन राठौड़, लुम्बाराम चौधरी, विधायक समाराम, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं आमजन उपस्थित थे।

पूर्व मुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ईडी की जांच उस कथित वित्तीय लेनदेन से जुड़ी है, जिसमें खनन कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) द्वारा वीणा की आईटी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो अब बन्द हो चुकी है, को 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने का आरोप है। जांच एजेंसी का दावा है कि यह राशि कंपनी को किसी सेवा के बदले नहीं दी गई थी। ईडी का आरोप है कि भुगतान के बावजूद एक्सालॉजिक ने कोई वास्तविक सेवा प्रदान नहीं की। इसी आधार पर एजेंसी इस पूरे लेनदेन को संदिग्ध मानते हुए मनी लॉण्डरिंग के पहलू की जांच कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक, 17 जून को हुई पहली पूछताछ के दौरान वीणा के बयान दर्ज किए गए थे। इसके बाद एजेंसी ने उपलब्ध दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण किया। जांच के दौरान कुछ और तथ्यों को स्पष्ट करने की जरूरत महसूस की गई, जिसके बाद ईडी ने वीणा को दोबारा तलब करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि अब तक इस मामले में चार अन्य आरोपियों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। 19 जून को ईडी अधिकारियों ने तिरुवनंतपुरम में वीणा के बैंक लॉकरों का भी निरीक्षण किया था।

रविवार को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। जंतर-मंतर पर भारी संख्या में एकत्रित प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तुरंत पद छोड़ने की मांग की है।

क्या इज़रायल का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमेरिकी पैट्रियट तथा थाड (टी.एच.ए.ए.डी.) रक्षा प्रणालियां भी इज़रायल की सुरक्षा मजबूत करने के लिए तैनात की गई हैं।

एकमात्र क्षेत्र, जहां इज़राइल वास्तव में आत्मनिर्भर माना जाता है, वह उसका रणनीतिक प्रतिरोधक (स्ट्रैटेजिक डिटरैंट) तंत्र है। इसमें स्वदेशी जेरिको-तीसरी मिसाइल प्रणाली और जर्मनी निर्मित पनडुब्बियां शामिल हैं, जो उसे समुद्र आधारित परमाणु क्षमता प्रदान करती हैं। हालांकि, उसके, देश में डिज़ाइन किए गए मर्कवा टैंक भी अमेरिका में बने इंजनों पर निर्भर हैं।

विशेषज्ञों की व्यापक राय है कि यदि अमेरिकी समर्थन अचानक समाप्त हो जाए तो इज़रायल को गंभीर झटका लगेगा। स्पेयर पार्ट्स की निरंतर आपूर्ति बंद होने पर उसकी वायु सेना के बड़े हिस्से को संचालित रखना कठिन हो जाएगा। लंबे संघर्ष की स्थिति में उसके गोला-बारूद के भंडार भी अपेक्षाकृत जल्दी समाप्त हो सकते हैं।

इज़रायल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व उपप्रमुख चक फ्राइलिच के अनुसार, यह निर्भरता केवल गोला-बारूद तक सीमित नहीं है, बल्कि सेना के लगभग हर स्तर तक फैली हुई है, यदि उन्हें डिलिवर करने के लिए अमेरिका से एयरक्राफ्ट मंगाने पड़ें।

लागत भी एक बड़ी बाधा है। फ्राइलिच ने 1980 के दशक में इज़रायल द्वारा अपना लड़ाकू विमान विकसित करने के असफल प्रयास का उदाहरण दिया। इस परियोजना पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग पांचवां हिस्सा खर्च हो गया था, लेकिन अंततः इसे बंद करना पड़ा।

पूर्व आईडीएफ उपप्रमुख उज़्ज़ी दयान ने भी यही राय व्यक्त की। उनका कहना था कि इज़रायल जैसी अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्था के लिए अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों का स्वतंत्र विकास आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। इज़रायल के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान की एक रिपोर्ट ने भी निष्कर्ष निकाला कि पूर्ण सैन्य आत्मनिर्भरता की बात व्यवहारिक दृष्टि से केवल एक कल्पना है।

यह निर्भरता केवल इज़रायल की अपनी सैन्य क्षमता को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि उन देशों को भी प्रभावित करती है जो उससे हथियार खरीदते हैं।

भारत ने लगभग बीस वर्ष पहले इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया था, जब ग्रीन पाइन रडार और फाल्कन हवाई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की खरीद के लिए अमेरिकी मंजूरी आवश्यक थी। हालांकि, ये इज़रायली टैक्नॉलजी के रुप में ब्रैण्डेड थे, लेकिन इन्हें अमरीकी कंपनियों के साथ मिलकर विकसित किया गया था। यरुशलम से चाहे जितने भी स्वतंत्रता के दावे किए जाएं, व्यावहारिक वास्तविकता यही है कि इज़रायल की रक्षा क्षमता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन अब भी वॉशिंगटन से गहराई से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के संबंधों में समय-समय पर तनाव आ सकता है, लेकिन दोनों पक्षों के पास इस साझेदारी को बनाए रखने के मजबूत कारण हैं। फिलहाल पूर्ण अलगाव की संभावना वास्तविकता से अधिक राजनीतिक बयानबाजी ही दिखाई देती है।

तुषार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तीन साल के कार्यकाल के लिए और फिर 2023 में पुनः नियुक्त किया। नवीनतम कार्यकाल विस्तार के साथ, मेहता सॉलिसिटर जनरल के रूप में लगभग आठ वर्ष पूरे कर चुके हैं और नए कार्यकाल के अंत तक इस पद पर 11 वर्ष पूरे करने वाले हैं, जिससे वे देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक इस पद पर सेवा देने वाले विधि अधिकारियों में से एक बन जाएंगे।

सॉलिसिटर जनरल के रूप में, मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कई महत्वपूर्ण संवैधानिक, नीतिगत और आपराधिक मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया है।

नीट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ।

जब परिजनों ने सख्ती से पूछा तो सिमरन ने बताया कि उसने घर में रखा कीटनाशक पी लिया है। इसके बाद परिजन उसे गंभीर हालत में हिसार के सर्वेश अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

पिता रोहताश ने बताया कि सिमरन को देखकर नहीं लगा कि वह आत्महत्या कर लेगी। वह नार्मल लग रही थी और उसने रातभर पढ़ाई भी की थी। सुबह उसने बताया था कि वह 11 बजे घर से पेपर देने के लिए निकलेगी। इससे पहले यह हादसा हो गया।

भारत की प्राचीन परम्परा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रखने का मार्ग दिखाता है। योग जीवनशैली में संतुलन लाता है तथा व्यक्ति को उम्र बढ़ने के बावजूद ऊर्जावान बनाए रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीकृष्ण ने भी गीता में योग के महत्व का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि समाज स्वस्थ होगा तो देश भी स्वस्थ बनेगा।

प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद रेड रोड पर सामूहिक योगाभ्यास शुरू हुआ। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में योग की पुरानी परंपरा रही है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति से राज्य में योग दिवस का आयोजन ऐतिहासिक बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में योग दिवस को लेकर सरकारी स्तर पर कोई विशेष पहल नहीं हुई, लेकिन अब राज्य में योग के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है।

रेड रोड पर मुख्य योग कार्यक्रम सुबह करीब 6:30 बजे शुरू हुआ। कार्यक्रम में लगभग 35 हजार लोगों के प्रधानमंत्री के साथ योगाभ्यास में शामिल होने की व्यवस्था की गई थी।

योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों की सुविधा के लिए रविवार तड़के से कोलकाता मेट्रो की सेवाएं शुरू कर दी गई थीं। ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन सहित, शहर की सभी मेट्रो लाइनों पर सुबह 4 बजे के कुछ समय बाद से सेवाएं चालू कर दी गईं, ताकि दूरदराज से आने वाले प्रतिभागी समय पर रेड रोड पहुंच सकें।

प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए, रेड रोड और आसपास के क्षेत्रों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए थे। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के लिए निर्धारित समय और सुरक्षा जांच की व्यवस्था की गई थी।

भाषण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बाकी नेता यहां कूड़ा उठाने आए हैं?" उन्होंने कार्यकर्ताओं को अनुशासन बनाए रखने की नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस में व्यक्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है और पार्टी किसी भी व्यक्ति से बड़ी है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई नेता कितना भी बड़ा क्यों न हो, संगठन सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी ने ही नेताओं को पहचान और ताकत दी है, इसलिए संगठन और अनुशासन को बनाए रखना सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है।

दिसम्बर में हो सकता है भारत व यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स से कहा कि यह समझौता फरवरी में लागू हो जायेगा

■ गोयल ने कहा कि लगभग शून्य शुल्क होने से स्थानीय उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा। यूरोपीय संघ से आने वाली लग्ज़री कारों व वाइन पर आयात शुल्क कम होने से ये उत्पाद भारत में सस्ते हो जायेंगे।

नई दिल्ली, 21 जून। भारत, और 27 देशों के संगठन यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता इस साल दिसंबर तक हस्ताक्षरित हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ बातचीत में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक समझौते को अगले साल फरवरी-मार्च के दौरान पूरी तरह लागू किए जाने की संभावना है।

इसी साल 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ ने वार्ता के निष्कर्ष की घोषणा की थी। इसे व्यापार की दुनिया में सभी समझौतों की मां (मदर ऑफ ऑल डील्स) कहा जा रहा है। पीयूष गोयल ने कहा कि अब लगभग शून्य शुल्क के साथ, पूरा यूरोपीय बाजार हमारे लिए खुल जाएगा। इस समझौते के लागू होते ही भारत के व्यापारिक रिश्तों को एक नई और अभूतपूर्व उड़ान मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि पूरी दुनिया इस समय भारत की तरफ बेहद उम्मीद से देख रही है। इस ऐतिहासिक भारत-ईयू समझौते के तहत, भारतीय खेपों (शिपमेंट्स) के लगभग 93 प्रतिशत हिस्से को यूरोपीय बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। इसका सीधा फायदा भारतीय निर्यातकों और स्थानीय उद्योगों को होगा।

इसके साथ ही, यूरोपीय संघ से भारत आने वाली लक्जरी कारों और वाइन पर आयात शुल्क कम होगा, जिससे ये उत्पाद भारत में सस्ते हो जाएंगे। आर्थिक आंकड़ों के लिहाज से यह बेहद मजबूत साझेदारी है। भारत और यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 25 प्रतिशत हिस्सा संभालते हैं। इसके अलावा, दोनों पक्ष अंतरराष्ट्रीय व्यापार (लगभग 33 ट्रिलियन डॉलर) का एक-तिहाई, यानी लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर, यानी करीब 10,38,52,380.5 करोड़ रुपये का प्रतिनिधित्व करते हैं।

गोवा अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई

सलगांवकर समूह और उसके सहयोगियों से जुड़ी 1,023.85 करोड़ की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया

■ कुर्क की गई संपत्तियों में भारत में स्थित 459.10 करोड़ रुपये मूल्य की 99 अचल संपत्तियां, सिंगापुर में स्थित 471.32 करोड़ रुपये मूल्य की 31 अचल संपत्तियां और भारतीय कंपनियों में 93.42 करोड़ रुपये मूल्य के इक्विटी शेयर शामिल हैं।

■ ईडी ने बताया कि एजेंसी की जांच में खुलासा हुआ कि एवीएस समूह ने वर्ष 2007 से 2012 के दौरान कुल दस खनन पट्टों का संचालन किया और लौह अयस्क के अवैध निष्कर्षण, बिक्री व निर्यात से लगभग 2,492.95 करोड़ की अपराध की कमाई अर्जित की।

नई दिल्ली, 21 जून। गोवा के अवैध लौह अयस्क खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सलगांवकर समूह और उसके सहयोगियों (एवीएस समूह) से जुड़ी 1,023.85 करोड़ की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है।

ईडी के पणजी आंचलिक कार्यालय ने 19 जून को जारी एक अंतरिम कुर्की आदेश के तहत यह कुर्की की। कुर्क की गई संपत्तियों में भारत में स्थित 459.10 करोड़ रुपये मूल्य की 99 अचल संपत्तियां, सिंगापुर में स्थित 471.32 करोड़ रुपये मूल्य की 31 अचल संपत्तियां और भारतीय कंपनियों में 93.42 करोड़ रुपये मूल्य के इक्विटी शेयर शामिल हैं। ये संपत्तियां स्वर्गीय अनिल वासुदेव सलगांवकर की संपत्ति (उनकी प्रशासनिक श्रीमती लक्ष्मी अनिल सलगांवकर के माध्यम से), मैसर्स सलगांवकर माइनिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स शांतिलाल खुशालदास एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एस कांतिलाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स सलीथो ओर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स वर्टेक्स न्यूटन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सुवर्णरेखा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत हैं। ईडी ने बताया कि एजेंसी ने गोवा पुलिस की सीआईडी अपराध शाखा द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर) के तहत दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी 21 अप्रैल, 2014 और 7 फरवरी, 2018 के अपने फैसलों में स्पष्ट किया था कि गोवा में 22 नवंबर 2007 के बाद (नए खनन पट्टे जारी होने तक) किया गया सारा खनन अवैध और बिना कानूनी अधिकार के था।

ईडी ने बताया कि एजेंसी की जांच में खुलासा हुआ कि एवीएस समूह ने वर्ष 2007 से 2012 के दौरान कुल दस खनन पट्टों का संचालन किया और लौह अयस्क के अवैध निष्कर्षण, बिक्री व निर्यात से लगभग 2,492.95 करोड़ की अपराध की कमाई अर्जित की।

अवैध रूप से निकाले गए इस अयस्क को बेहद कम कीमतों पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) में पंजीकृत शेल कंपनियों को निर्यात किया गया था।

जेलेंस्की ने पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान लौटाया

वारसा, 21 जून। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल लौटा दिया। जेलेंस्की ने यह कदम पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नावरोकी द्वारा यह सम्मान उनसे वापस लेने की घोषणा के बाद उठाया है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से सम्मान वापस लेने का एलान द्वितीय विश्वयुद्ध की घटना को लेकर पैदा विवाद के चलते किया गया। इस विवाद में जेलेंस्की का यूक्रेनी सेना की एक यूनिट का नाम उस अर्धसैनिक बल के नाम पर रखने का निर्णय है जिसने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान पोलैंड में लोगों का नरसंहार किया था। जेलेंस्की ने बीती 26 मई को यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स का नाम यूक्रेनियन इंसरजेंट आर्मी रखने का निर्णय लिया था। जबकि इसी आर्मी ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान पोलैंड में बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं की थीं। उल्लेखनीय है कि 2023 में पोलैंड के तत्कालीन राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान से जेलेंस्की को सम्मानित किया था।

उद्धव गुट के सांसद नागेश आष्टीकर ने शिंदे का दामन थामा

पिछले कई दिनों से उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें लग रही थीं, जिन पर उन्होंने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी

■ सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया है। उनका कहना था कि वह एक शिवसेना से दूसरी शिवसेना में गए हैं। उन्होंने दावा किया कि 18 जून तक उन्होंने और कुछ अन्य सांसदों ने कोई फैसला नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।

छत्रपति संभाजीनगर, 21 जून। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (यूबीटी) को बड़ा झटका देते हुए हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर ने रविवार को साफ कर दिया कि वह अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ हैं। पिछले कई दिनों से उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें लग रही थीं, जिन पर उन्होंने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया है। उनका कहना था कि वह एक शिवसेना से दूसरी शिवसेना में गए हैं। उन्होंने दावा किया कि 18 जून तक उन्होंने और कुछ अन्य सांसदों ने कोई फैसला नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।

हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की ओर था। संजय राउत ने बागी सांसदों के खिलाफ कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया था और 'ऑपरेशन तुड़वा' की चेतावनी भी दी थी। आष्टीकर ने कहा कि किसी को नाराजगी जाहिर करने का अधिकार है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।

सांसद ने पार्टी छोड़ने के पीछे विकास कार्यों के लिए धन की कमी को भी बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में होने के कारण क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे और कार्यकर्ताओं के काम भी नहीं हो पा रहे थे।

कीर स्टार्मर पर इस्तीफे का दबाव: जा सकती है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कुर्सी

लेबर पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है, पार्टी नेता अब एंडी बर्नहैम को नया प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं

■ हाल ही में मेकरफील्ड सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस चुनाव में बर्नहैम ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने धुर दक्षिणपंथी नेता नाइजेल फराज की पार्टी रिफॉर्म यूके को बुरी तरह हरा दिया। इस जीत के बाद बर्नहैम की दावेदारी सबसे मजबूत हो गई है।

लंदन, 21 जून। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की कुर्सी खतरे में है। उन पर पद छोड़ने का भारी दबाव है। लेबर पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। पार्टी नेता अब एंडी बर्नहैम को नया प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हाल ही में मेकरफील्ड सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस चुनाव में बर्नहैम ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने धुर दक्षिणपंथी नेता नाइजेल फराज की पार्टी रिफॉर्म यूके को बुरी तरह हरा दिया। इस जीत के बाद बर्नहैम की दावेदारी सबसे मजबूत हो गई है।

लेबर पार्टी के भीतर अब खुलकर विरोध होने लगा है। स्टार्मर की अपनी कैबिनेट के मंत्री भी उनके खिलाफ हो गए हैं। लंदन के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। कयास हैं कि स्टार्मर अगले हफ्ते ही प्रधानमंत्री आवास खाली कर सकते हैं। हालांकि स्टार्मर अभी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। शनिवार को उन्होंने पत्रकारों से बात की। स्टार्मर ने कहा कि दो साल पहले जनता ने उन्हें बड़ा जनादेश दिया था। वह देश की सेवा के लिए चुने गए थे। उन्होंने साफ कहा कि वह मैदान छोड़कर कहीं नहीं भागेंगे।

स्टार्मर भले ही अपनी जिद पर अड़े हैं, लेकिन उनकी पकड़ कमजोर हो चुकी है। दूसरी तरफ एंडी बर्नहैम ने अपनी नई कैबिनेट बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है।?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 300 लेबर सांसद बर्नहैम के साथ हैं। व्यापार सचिव पीटर काइल ने रविवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्टार्मर को राजनीतिक हकीकत को समझना होगा।

नीतीश कुमार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुने जायेंगे

पटना, 21 जून। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को राजधानी पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय परिषद ने सर्वसम्मति से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का अनुमोदन किया। इस दौरान संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति तथा पार्टी के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जदयू के लिए यह गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उनके निर्वाचन का औपचारिक अनुमोदन किया गया। इससे पूरे संगठन और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है तथा पार्टी को नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि रविवार को आयोजित राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठकों में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की सक्रिय भागीदारी भी चर्चा का विषय रही।

नीट-यूजी : 22 लाख से अधिक छात्रों ने कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच दी परीक्षा

परीक्षा देश भर के 551 शहरों के 5440 परीक्षा केंद्रों और विदेशों के 14 शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर एक साथ आयोजित की हुई है।

■ हिंदी, अंग्रेजी सहित कुल 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित नीट-यूजी की परीक्षा पर केंद्रीय एजेंसियों के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पैनी नजर रखी।

नई दिल्ली, 21 जून। मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले से जुड़ी नीट-यूजी की परीक्षा रविवार को दोबारा देश भर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई और शिक्षा मंत्रालय के लिए राहत रही कि कहीं से किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। इसके साथ ही 22 लाख से अधिक छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना भी ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन) सीट में कैद हो गया।

इससे पहले यह परीक्षा तीन मई को हुई थी, लेकिन बाद में पेपर लीक का मामला सामने के बाद पूरी परीक्षा को रद कर दिया गया था। साथ ही इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। यह जांच अभी चल रही है। एनटीए के मुताबिक नीट यूजी की दोबारा परीक्षा देश भर के 551 शहरों के 5440 परीक्षा केंद्रों और विदेशों के 14 शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर एक साथ आयोजित की हुई है।

एनटीए ने सभी केंद्रों पर परीक्षा तय प्रोटोकॉल के मुताबिक कराए जाने का होने का दावा किया है। साथ ही बताया कि ओएमआर सीट को भी प्रश्न पत्रों की तरह सुरक्षा के कड़े प्रोटोकाल में लाया जा रहा है, इनमें भी भारतीय वायु सेना व भारतीय डाक विभाग की मदद ली जा रही है। परीक्षा माफिया की सक्रियता व परीक्षा को लेकर फैलाए जा रहे झूठ और दुष्प्रचार को देखते हुए एनटीए ने परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्थानीय पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती दी गई थी। साथ ही प्रत्येक शहरों में साइबर कमांडो भी तैनात किए थे।

हिंदी, अंग्रेजी सहित कुल 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित नीट-यूजी की परीक्षा पर केंद्रीय एजेंसियों के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पैनी नजर रखी। परीक्षा के दौरान वह एनटीए मुख्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम में पहुंचे और वहां से सीसीटीवी के जरिए परीक्षा पर नजर रखे। साथ ही वहां तैनात टीमों को भी सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए।

नीट-यूजी की रविवार को दोबारा हुई परीक्षा में छात्रों को इस बार पंद्रह मिनट अतिरिक्त समय दिया गया था। वैसे तो परीक्षा में छात्रों को अब तक तीन घंटे का समय दिया जाता था, जिसमें उन्हें परीक्षा से जुड़ी कागजी कार्रवाई के साथ ही प्रश्नपत्र को हल करना होता था। हालांकि इस बार छात्रों के हितों को देखते हुए एनटीए ने परीक्षा के दौरान होने वाली कागजी कार्रवाई के लिए पंद्रह मिनट अतिरिक्त समय दिया था। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने इस बार परीक्षा के दौरान मिले पंद्रह मिनट के अतिरिक्त समय को लेकर खुशी जताई। ऐसे में दोपहर दो बजे से शुरू हुई परीक्षा शाम 5.15 बजे खत्म हुई।

नीट-यूजी परीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी छात्रों की सुविधा का ध्यान रखा।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908